www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष – 04 | अंक – 298 | जौनपुर शुक्रवार, 19 जून 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

टीवीके सरकार के तहत तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र

चेन्नई, (एजेंसी)। टीवीके के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के गठन के बाद तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र गुरुवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। यह नई सरकार के विधायी कार्यकाल की औपचारिक शुरुआत होगी। नवनिर्वाचित विधानसभा की पहली बैठक होने के कारण सत्र की शुरुआत परंपरागत राज्यपाल अभिभाषण से होगी, जिसमें सरकार की नीतियों, कल्याणकारी योजनाओं और विकास संबंधी प्राथमिकताओं की रूपरेखा पेश की जाएगी।विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने राज्यपाल आर्लेकर को सत्र का उद्घाटन करने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। राज्यपाल सुबह 9रू50 बजे फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित विधानसभा परिसर पहुंचेंगे, जहां उन्हें सचिवालय भवन के दूसरे द्वार पर औपचारिक स्वागत दिया जाएगा। अध्यक्ष प्रभाकर और विधानसभा सचिव श्रीनिवासन राज्यपाल का स्वागत करेंगे और उन्हें विधानसभा कक्ष तक लेकर जाएंगे। राज्यपाल लाल कालीन पर चलते हुए सदन में प्रवेश करेंगे और अंग्रेजी में अपना अभिभाषण देंगे। इसके बाद अध्यक्ष द्वारा भाषण का तमिल अनुवाद पढ़ा जाएगा।राज्यपाल के अभिभाषण में टीवीके सरकार की आगामी वर्षों की प्रमुख योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का उल्लेख होने की संभावना है। यह भाषण विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद सरकार की प्राथमिकताओं का संकेत भी देगा।

वाईएसआरसीपी ने एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप लगाया

अमरावती, (एजेंसी)। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर मतदाता नाम हटाने के लिए किया जा रहा है। पार्टी नेता और पूर्व मंत्री साके शैलजानाथ ने कहा कि चल रही एसआईआर प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हो गई है। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ गठबंधन एक बार फिर मतदाता नाम हटाने के लिए श्मायटीडीपी ऐपश का इस्तेमाल कर रहा है।ताडेपल्ली स्थित वाईएसआरसीपी केंद्रीय कार्यालय में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता की बार–बार मांग की है और ऐप के माध्यम से मतदाता डेटा संग्रह और दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है।उन्होंने याद दिलाया कि पहले के सेवा मित्र अभियान के दौरान, लगभग 30 लाख वाईएसआरसीपी वोटों को हटाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बाद में कानूनी हस्तक्षेप के माध्यम से उन्हें बचा लिया गया था। बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया ।

जी-7 में पीएम मोदी ने रखा एआई पर भारत का 'मानव' विजन, सुरक्षा और समावेशिता पर जोर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फ्रांस के एवियन में आयोजित जी–7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में "इंश्योरिंग ए सेफ, रैपिड एंड एफिशिएंट रोल आउट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक परिवर्तनकारी शक्ति है, जो मानव सभ्यता की दिशा को नए सिरे से परिभाषित करने की क्षमता रखती है, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक सोच के साथ भारत ने हाल ही में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी की थी। उन्होंने एआई के लिए भारत के 'मानव' विजन को रेखांकित करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास समावेशिता, सुरक्षा और जनहित जैसे मूल सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, ताकि तकनीक का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हमेशा साइबरस्पेस को एक वैश्विक सार्वजनिक संपत्ति के रूप में देखता रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक देशों के पास ऐसे एआई मॉडल तक पहुंच होनी चाहिए, जो उनके महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा कर सकें और साइबर खतरों से निपटने में मददगार साबित हों। एआई के सुरक्षित, तेज और प्रभावी विकास के लिए प्रधानमंत्री ने एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने इस दिशा में चार महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि एआई प्रणालियां 'सेफ–बाय–डिजाइन' सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, यानी उनके निर्माण के स्तर पर ही सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही एआई के उपयोग के लिए समान मानक, परीक्षण ढांचा और नियामक दिशानिर्देश विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने डीपफेक, गलत सूचना और साइबर धोखाधड़ी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी वैश्विक सहयोग का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एआई के लाभ केवल विकसित देशों तक सीमित नहीं रहने चाहिए।

जनजातीय समुदायों की जीवनशैली आध्यात्मिक मूल्यों के अनुरूप – राष्ट्रपति मुर्मु

मध्य प्रदेश, (एजेंसी)। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के बैतूल में आयोजित 'आध्यात्मिक जागरण द्वारा जनजातीय समाज का सशक्तिकरण' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि आज की तेज रफ्तार और उपभोक्तावादी संस्कृति से प्रभावित दुनिया में समाज के हर वर्ग के लिए आध्यात्मिक शुद्धता बेहद जरूरी हो गई है। इसी आधार पर समानता पर आधारित आचरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील जीवनशैली विकसित की जा सकती है, जो लंबे समय तक टिकाऊ हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया तनाव और संघर्षों से घिरी हुई है, ऐसे में 'आध्यात्मिक जागरण द्वारा जनजातीय समाज का सशक्तिकरण' जैसे सम्मेलन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदायों की जीवनशैली स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक मूल्यों के अनुरूप होती है। उनका प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों से गहरा जुड़ाव उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सार्वभौमिक कल्याण की भावना के साथ जीने की प्रेरणा देता है। उन्होंने खुशी जताई कि ब्रह्माकुमारी संस्था लंबे समय से इसी सोच के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय समुदायों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि भारतीय जीवन मूल्यों के अनुरूप काम करने वाले किसी भी संगठन को यह समझना चाहिए कि समाज के किसी वर्ग का सशक्तिकरण केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं हो सकता।

योगी का सपा–कांग्रेस पर तीखा हमला, उन्नाव से कानपुर तक दिखेगा विकास

उन्नाव, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भवानखेड़ा गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह रामायण काल में खर–दूषण थे, वैसे ही सपा–कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश में माफिया राज था। उन्होंने कहा, दंगा और माफिया ग्रस्त प्रदेश बनाने वाले लोग आज विकास पर उपदेश दे रहे हैं, जिनका दोहरा चरित्र देखकर हंसी आती है। मुख्यमंत्री ने जिले वासियों को विकास परियोजनाओं की बधाई देते हुए कहा कि अब उन्नाव की कनेक्टिविटी फोरलेन की हो गई है। उन्होंने कहा कि अब उन्नाव से दिल्ली और प्रयागराज के लिए सबको बायपास करके आसानी से पहुंचा जा सकता है। उन्नाव में तेजी से औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे, जिससे जिले के युवाओं को अब रोजगार के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, उन्हें यहीं काम मिलेगा। सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज शौचालय, आवास, पेंशन, गैस कनेक्शन और आयुष्मान भारत योजना का लाभ बिना किसी सिफारिश के सीधे गरीबों तक पहुंच रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार के 10–12 वर्षों के काम की तुलना सपा–कांग्रेस से करते हुए कहा कि जो काम भाजपा ने किया है, वह ये दल कभी नहीं कर पाएंगे। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने पुरानी कहावत का जिक्र करते हुए सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले नारा था– देख सपाई और बिटिया–बहू घबराई।

तकनीकी कौशल ही सफलता की कुंजी, युवाओं को एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्र अपनाने की सलाह : सीएम सरमा

असम, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को छात्रों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं से भविष्य के रोजगार बाजार को ध्यान में रखते हुए अपने करियर की योजना बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ग्रीन एनर्जी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र आने वाले वर्षों में रोजगार के प्रमुख स्रोत बनेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर किए गए एक संदेश में मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषित कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों का उल्लेख करते हुए छात्रों को बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप अपने करियर का चयन करने की सलाह दी। उन्होंने लिखा, "अगर आपके 12वीं के नतीजे आ गए हैं और आप अपने करियर की अगली दिशा तय कर रहे हैं, तो उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जो आने वाले समय में असम के रोजगार बाजार को आकार देंगे। अवसरों की कोई कमी नहीं होगी, बस खुद को उनके लिए तैयार रखें।" मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट के साथ "असम के युवाओं को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करना" शीर्षक वाला एक इन्फोग्राफिक भी साझा किया, जिसमें उन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें राज्य सरकार भविष्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का आधार मान रही है। इन्फोग्राफिक के अनुसार, सेमीकंडक्टर उद्योग में चिप निर्माण और उससे जुड़े क्षेत्रों में नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। यह क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत के लिए एक नई शुरुआत माना जा रहा है। जगीरोड (मोरीगांव जिला) में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग यूनिट स्थापित होने के बाद असम सेमीकंडक्टर निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को भी तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र बताते हुए कहा कि इससे तकनीक और डेटा आधारित करियर के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं, सौर ऊर्जा, जलविद्युत और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं सहित ग्रीन एनर्जी सेक्टर को भी रोजगार की अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र बताया गया।

दिल्ली में 42 जन कल्याण शिविर, 20 जून तक सुनी जाएंगी शिकायतें

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल और दिल्ली सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर तीन दिवसीय श्जन कल्याण शिविरश का आयोजन किया गया है। इस शिविर में दिल्ली के लोग अपनी समस्याओं को लेकर जा सकते हैं, जहां पर उनका समाधान किया जाएगा। हर विभाग की ओर से इस शिविर के तहत काउंटर स्थापित किए गए हैं, जहां लोग अपनी समस्याओं को लेकर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इस बारे में पत्रकारों से बातचीत में जानकारी दी। उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के मौके पर इस शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर 18, 19 और 20 जून को आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। दिल्ली में 42 जगहों पर इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के तहत हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं का लाभ दिल्ली के लोगों को मिल रहा है की नहीं? अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो निश्चित तौर पर उसका समाधान करने की दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को पेंशन योजना, राशन कार्ड की सुविधा, लेबर कार्ड, स्वनिधि योजना और मुद्रा योजना जैसी योजनाओं का लाभ मिले। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगी, तो उसका फौरन निदान किया जाएगा। सभी विभागों की ओर से काउंटर स्थापित करके लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। हम जनता की सेवा करने के लिए इस तरह के शिविर का आयोजन कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली तेज गति से आगे बढ़े। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के मौके पर प्रतिक्रिया दी। उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी के जनविश्वास के 12 साल पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को फायदा पहुंचाने के लिए 40 योजनाओं को शुरू करके उसे मूर्त रूप देने का काम किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि जनता को इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति उन योजनाओं का लाभ मिला है।

नवाचार और तकनीक के दम पर एआई महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा भारत – पीयूष गोयल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि देश की युवा आबादी, सस्ता डेटा, बढ़ती तकनीकी क्षमताएं और समावेशी विकास का दृष्टिकोण भारत को वैश्विक तकनीकी क्रांति में अग्रणी स्थान पर पहुंचा रहा है। विवा टेक 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दौर में भारत की भूमिका पर बोलते हुए गोयल ने कहा कि भारत के पास कई ऐसी प्राकृतिक ताकतें हैं, जो उसे वैश्विक तकनीकी अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने योग्य बनाती हैं। उन्होंने कहा कि भारत कई देशों की तुलना में तकनीक को अधिक तेजी और प्रभावी ढंग से अपनाता है तथा एआई को खतरे के बजाय विकास का माध्यम मानता है। गोयल ने कहा, "भारत दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। हमारी युवा और प्रतिभाशाली आबादी, सस्ता डेटा, बढ़ती क्षमताएं और साझा विकास का दृष्टिकोण हमें तकनीकी विकास की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करता है।" केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि एआई कभी भी मानव बुद्धिमत्ता, मानवीय मूल्यों, संस्कृति और परंपराओं का स्थान नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। देश की औसत आयु 30 वर्ष से कम है, जो उसे अन्य देशों की तुलना में विशेष बढ़त देती है। गोयल ने कहा, "हमारे पास युवा आबादी है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी औसत आयु 30 वर्ष से कम है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था हैं।

छात्रों की गूंज अभियान के जरिए राहुल गांधी ने छात्रों से मांगे सुझाव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर एक नया अभियान शुरू किया है। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए युवाओं और छात्रों से श्छात्रों की गूंजश अभियान से जुड़ने की अपील की। राहुल गांधी ने श्एक्सश पोस्ट में उन छात्रों को संबोधित किया, जिन्होंने पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली या बढ़ती फीस जैसी समस्याओं का सामना किया है। उन्होंने श्एक्सश पोस्ट के जरिए कहा कि यदि किसी छात्र के सपने इस व्यवस्था की वजह से टूटे हैं या उनके परिवार ने पढ़ाई के लिए अपनी जीवनभर की कमाई लगा दी है, तो छात्रों की गूंज उनकी आवाज बनने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि छात्रों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है। राहुल गांधी के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य छात्रों के लिए सस्ती शिक्षा, निष्पक्ष परीक्षाएं और सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की मांग को मजबूती देना है। अपने एक्स पोस्ट में राहुल गांधी ने छात्रों से इस अभियान में हिस्सा लेने की अपील करते हुए बताया कि इसमें जुड़ने में केवल 30 सेकंड का समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इच्छुक छात्र और युवा सबसे पहले दिए गए आधिकारिक लिंक पर जाएं, फिर अपना नाम दर्ज करें और अपने सुझाव शेयर करें। इसके बाद ऑनलाइन याचिका (पिटिशन) पर हस्ताक्षर कर अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हर एक हस्ताक्षर इस लड़ाई को मजबूत बनाएगा और जितने अधिक लोग इस अभियान से जुड़ेंगे, छात्रों की आवाज उतनी ही बुलंद होगी।

नीट परीक्षा में अभिभावकों के लिए बनाए जाएंगे कूलिंग जोन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देशभर में 21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने अभूतपूर्व और बड़ी पहल करते हुए न केवल नीट परीक्षार्थियों बल्कि उनके साथ आने वाले अभिभावकों की सुविधा का भी विशेष प्रबंध किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहली बार है जब परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वालों के साथ–साथ उनके माता–पिता और परिजनों के आराम एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए कूलिंग जोन बनाए जा रहे हैं, जहां उनके बैठने की सुविधा, स्वच्छ पेयजल, शिकंजी आदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में नीट परीक्षा के लिए कुल 97 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 69 सरकारी विद्यालयों में तथा 28 केंद्रीय विद्यालयों में हैं। इन परीक्षा केंद्रों के आसपास जिला प्रशासन द्वारा विशेष कूलिंग जोन स्थापित किए जा रहे हैं, जहां अभिभावकों और परिजनों के बैठने, विश्राम करने तथा गर्मी से राहत पाने की समुचित व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष लाखों परिवार अपने बच्चों के भविष्य के सपनों के साथ परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते हैं। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी तो केंद्र के भीतर होते हैं, लेकिन बाहर कई घंटे तक प्रतीक्षा कर रहे माता–पिता की चिंता, धूप, गर्मी और असुविधा पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। दिल्ली सरकार ने इस मानवीय पहलू को समझते हुए यह निर्णय लिया है कि परीक्षा के दिन अभिभावकों को असुविधा का सामना न करना पड़े। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अब तक अक्सर देखा जाता था कि परीक्षा के दौरान परिजन कभी किसी पेड़ की छांव तलाशते थे, कभी पार्क में बैठकर समय बिताते थे, तो कभी आसपास की बाजारों में इधर–उधर भटकते रहते थे। कई लोगों को भीषण गर्मी में लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता था। अब ऐसी स्थिति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर ही उनके लिए आरामदायक प्रतीक्षा व्यवस्था उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि डिविजनल कमिश्नर (डीएम) के निर्देश से संबंधित अधिकारी सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास कूलिंग जोन की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। इन कूलिंग जोन में बैठने की सुविधा, स्वच्छ पेयजल, शिकंजी, ओआरएस, चाय तथा प्राथमिक चिकित्सा जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी ताकि अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

संपादकीय

तेल खरीदना महंगा

पिछले महीने भारत यात्रा के लिए रवाना होने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एलान किया था कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति जल्द ही नई दिल्ली जाएंगी और भारत वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदेगा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज पांच दिन की भारत यात्रा आई हैं। संभावना है कि उनकी इस यात्रा के दौरान भारत वेनेजुएला से कच्चे तेल की अधिक खरीदारी का सौदा करेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने के आखिर में भारत यात्रा के लिए रवाना होने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस संबंध में एलान किया था। कहा था कि रोड्रिगेज जल्द ही नई दिल्ली जाएंगी और भारत वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदेगा। इस घोषणा की पृष्ठभूमि गौरतलब है। पिछले तीन जनवरी को वेनेजुएला पर अचानक हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकलस मदुरो और उनकी पत्नी का अपहरण करने के बाद अमेरिका ने वहां के तेल भंडार पर अपना पूरा नियंत्रण बना लिया है। अब अमेरिकी कंपनियां वहां तेल निकालने और बिक्री करने में जुटी हुई हैं। इस बिक्री का पैसा भी अमेरिका के पास जाता है, जो उसमें से वेनेजुएला का हिस्सा अपनी मर्जी से तय कर उसके खजाने में भेज देता है। रोड्रिगेज वेनेजुएला में चाविस्मो (पूर्व राष्ट्रपति उगो चावेज की समर्थक विचारधारा) का प्रमुख चेहरा रही हैं। मगर तीन जनवरी की घटना के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका द्वारा वहां थोपी गई औपनिवेशिक किस्म की व्यवस्था में उन्होंने काम करना स्वीकार किया है। इस बारे में लैटिन अमेरिकी वामपंथी समूहों में अलग– अलग राय है। एक सोच है कि ऐसा कर रोड्रिगेज आगे और हमलों और इस क्रम में चाविस्मो के सांगठनिक ढांचे को पूरी तरह नष्ट हो जाने से बचा रही हैं। इसे एक तरह की समय काटने की रणनीति बताया गया है। मगर उनके आलोचकों की संख्या भी कम नहीं है। उधर यह भी कम विचित्र नहीं है कि भारत की तेल खरीद संबंधी फैसले अमेरिका ले रहा है। रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदना भारत को महंगा पड़ रहा है। मगर डॉनल्ड ट्रंप के काल में अमेरिका से रिश्ता रखने के लिए ऐसी कीमतें चुकाने की अनिवार्य शर्त उसके सभी कथित सहयोगी देशों को चुकानी पड़ रही है। भले बात परेशान करने वाली हो, लेकिन यही सच है कि रोड्रिगेज की भारत यात्रा का एजेंडा वॉशिंगटन से तय हुआ है।

विश्व शांति एवं संतुलन के लिए आत्ममंथन हो जी–7 बैठक में

ललित

फ्रांस में आयोजित जी–7 शिखर सम्मेलन पर इस समय पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा सुरक्षा और युद्ध जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए दुनिया की सात प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का यह मंच एकत्रित हुआ है। ऐसे समय में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या जी–7 आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है, जितना उसकी स्थापना के समय था? क्या यह संगठन वास्तव में वैश्विक समस्याओं के समाधान का मंच बन पाया है अथवा यह कुछ शक्तिशाली देशों के हितों की रक्षा का माध्यम बनकर रह गया है? क्या इस मंच की प्रासंगिकता एवं उपयोगिता को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने स्वार्थों के चलते धुंधलाने में लगे हैं? विश्व में शांति स्थापना, संतुलित आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बने विभिन्न वैश्विक संगठनों की सफलता का मूल्यांकन उनके परिणामों से होता है, न कि उनके घोषणापत्रों से। दुर्भाग्य से जी–7 के संदर्भ में यह प्रश्न बार–बार उठता रहा है कि उसके निर्णयों और घोषणाओं का वास्तविक प्रभाव कितना है। पिछले वर्षों में रूस–यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का संकट, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन की चुनौती और बढ़ती व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जैसी समस्याओं के समाधान में यह संगठन अपेक्षित भूमिका निभाने में सफल नहीं दिखा है। जी–7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसकी दिशा और नीति निर्धारण पर अमेरिका का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है। विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति ने सहयोग के बजाय दबाव और वर्चस्व की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों के साथ भी कई बार ऐसा व्यवहार किया है, मानो वे साझेदार नहीं बल्कि अमेरिकी नीतियों का अनुसरण करने वाले अनुयायी हों। टैरिफ युद्ध, व्यापारिक प्रतिबंध, रक्षा व्यय को लेकर दबाव और अनेक एकतरफा निर्णयों ने सदस्य देशों के बीच अविश्वास बढ़ाया है। विशेषतः ईरान– इजरायल युद्ध ने समूची दुनिया की अर्थव्यवस्था का धराशायी कर दिया और यह अब अमेरिका के कारण ही हुआ है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हिंसक संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को एक व्यापक युद्ध की आशंका से भर दिया था। ईरान, इजरायल और इस क्षेत्र के अनेक गैर–राज्यीय समूह आमने–सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होर्मुज जलमार्ग बन गया था, जहां से विश्व के लगभग पांचवें हिस्से का तेल गुजरता है। जी–7 समूह के देश भी इसको लेकर बंटे हुए थे। यही कारण है कि जी–7 के भीतर आज पहले जैसी एकजुटता दिखाई नहीं देती। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और जापान जैसे देश कई मुद्दों पर अमेरिका से अलग दृष्टिकोण रखते हैं। ईरान युद्ध ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रश्न पर, वैश्विक व्यापार के नियमों पर और बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका को लेकर भी मतभेद सामने आते रहे हैं। ऐसे में यह अपेक्षा करना कठिन है कि यह संगठन विश्व की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए कोई सर्वमान्य और प्रभावी रणनीति प्रस्तुत कर पाएगा। इस सम्मेलन में भारत की उपस्थिति विशेष महत्व रखती है। भारत भले ही जी–7 का सदस्य न हो, लेकिन उसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति, वैश्विक प्रतिष्ठा और विकासशील देशों के प्रतिनिधि स्वरूप ने उसे इस मंच का एक महत्वपूर्ण सहभागी बना दिया है। यह अवसर केवल भारत की उपलब्धियों को प्रस्तुत करने का नहीं, बल्कि उन विकासशील और निर्धन देशों की आकांक्षाओं को मुखर करने का भी है, जिनकी आवाज अक्सर वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में दब जाती है। आज अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अनेक देश आर्थिक संकट, खाद्य असुरक्षा, जलवायु आपदाओं और ऋण के बोझ से जूझ रहे हैं। उनकी प्राथमिकताएं जी–7 देशों की प्राथमिकताओं से भिन्न हैं। इसलिए भारत को यह प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या विश्व की दिशा तय करने का अधिकार केवल कुछ विकसित देशों तक सीमित रहना चाहिए? क्या वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक, समावेशी और प्रतिनिधिक नहीं बनाया जाना चाहिए? यह

समय विकासशील देशों की आवाज को मजबूती देने और वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की चिंताओं को केंद्र में लाने का है। जी–7 की प्रासंगिकता पर सबसे बड़ा प्रश्न उसकी प्रभावशीलता को लेकर है। यदि कोई संगठन विश्व की प्रमुख समस्याओं को रोकने या सुलझाने में सक्षम नहीं है, तो उसकी उपयोगिता स्वतः प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। रूस–यूक्रेन युद्ध वर्षों से जारी है। पश्चिम एशिया लगातार अशांत बना हुआ है। आतंकवाद और कट्टरता की चुनौतियां बनी हुई हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया अभूतपूर्व संकटों का सामना कर रही है। इसके बावजूद वैश्विक नेतृत्व देने का दावा करने वाले मंचों की उपलब्धियां सीमित दिखाई देती हैं। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने तथा शांति और सहमति की दिशा में बढ़ने की खबरों ने पूरी दुनिया को राहत दी है। लंबे समय से चल रहे तनाव के कारण पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ रही थी और इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा था। जैसे ही दोनों देशों के बीच समझौते और संवाद की संभावनाएं मजबूत हुईं, दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में सकारात्मक संकेत दिखाई दिए। निवेशकों का विश्वास बढ़ा, ऊर्जा बाजार में स्थिरता के संकेत मिले और तेल की कीमतों में नरमी आई। इससे स्पष्ट है कि शांति केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं होती, बल्कि उसका सीधा संबंध वैश्विक आर्थिक स्थिरता और आम नागरिक के जीवन से भी होता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यदि संवाद और समझौता ही अंततः समाधान का मार्ग था, तो फिर टकराव और तनाव की स्थिति को इतना लंबा क्यों खींचा गया? आखिर राष्ट्रपति ट्रंप को समझौते और सहमति के लिए राजी होने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्या इसके पीछे आर्थिक दबाव थे? क्या वैश्विक बाजारों की चिंता थी? क्या अमेरिकी जनता की अपेक्षाएं थीं? या फिर यह स्वीकारोक्ति थी कि युद्ध और दबाव की राजनीति की भी सीमाएं होती हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर जी–7 जैसे मंचों में गंभीर चर्चा होनी चाहिए। विश्व समुदाय केवल औपचारिक शांति समझौतों से संतुष्ट नहीं हो सकता। आवश्यकता इस बात की है कि शांति स्थायी, विश्वसनीय और न्यायपूर्ण हो। यदि समझौते केवल राजनीतिक छवि निर्माण, चुनावी लाभ या अस्थायी रणनीतिक उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, तो वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते। जी–7 को यह सुनिश्चित करने की दिशा में पहल करनी चाहिए कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले शांति प्रयास वास्तविक हों और उनका उद्देश्य मानवता के हितों की रक्षा करना हो। आज वैश्विक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। दुनिया अब एकध्रुवीय नहीं रही। भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक शक्ति संतुलन को नया स्वरूप दे रही हैं।

अमेरिका-ईरान समझौता - शांति या अस्थायी विराम

असद

इस समझौते को संकट का अंत नहीं, बल्कि एक लंबी और जटिल कूटनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। इसकी सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, भरोसेमंद सत्यापन व्यवस्था, परस्पर प्रतिबद्धताओं के पालन और क्षेत्रीय तनावों के प्रबंधन पर निर्भर करेगी। इसने युद्ध के तत्काल खतरे को कम किया है और क्षेत्रीय स्थिरता की उम्मीद जगाई है। राजनीतिक विश्लेषण पॉडकास्ट अमेरिका और ईरान के बीच हुआ प्रारूप शांति समझौता पश्चिम एशिया में व्यापक युद्ध के तत्काल खतरे को कम करने में सफल रहा है। कई महीनों तक चले सैन्य टकराव ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित किया, होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा को खतरे में डाला और पूरे क्षेत्र में बड़े संघर्ष की आशंकाएं पैदा कर दी थीं। ऐसे माहौल में वाशिंगटन और तेहरान का बातचीत का रास्ता चुनना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इतिहास बताता है कि शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना और उसे लंबे समय तक कायम रखना दो अलग बातें हैं। यह समझौता फिलहाल किसी व्यापक शांति संधि से अधिक एक राजनीतिक समझ है, जिसका उद्देश्य संघर्ष रोकना और आगे की बातचीत के लिए रास्ता बनाना है। इसकी सफलता केवल अमेरिका और ईरान की प्रतिबद्धताओं पर नहीं, बल्कि इजराइल के रुख, घरेलू राजनीतिक विरोध और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े विवादों पर भी निर्भर करेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी कूटनीतिक और सैन्य रणनीति की सफलता बताया है। उनका कहना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य के फिर से खुलने से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में भरोसा लौटेगा। तेल आपूर्ति और समुद्री परिवहन को लेकर चिंताएं पहले ही कम हुई हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस समझौते का स्वागत करते हुए पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता लौटने की उम्मीद जताई है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह क्षेत्र विशेष महत्व रखता है।अमेरिकी नीति में भी एक बदलाव दिखाई देता है। पहले वाशिंगटन की मांग थी कि ईरान अपनी परमाणु क्षमताओं को पूरी तरह समाप्त करे, तभी प्रतिबंधों में राहत संभव होगी। मौजूदा समझौते में पहले सैन्य टकराव रोकने और बाद में परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों तथा क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत जारी रखने का रास्ता अपनाया गया है। हालिया संघर्ष ने यह भी दिखाया कि लंबे क्षेत्रीय युद्ध की आर्थिक और राजनीतिक कीमत काफी अधिक होती है।ईरान के भीतर भी अमेरिका को लेकर गहरा अविश्वास मौजूद है। 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने को वहां आज भी एक बड़ी वजह माना जाता है। यही कारण है कि तेहरान भविष्य की किसी भी व्यवस्था में अधिक ठोस गारंटी चाहता है। भारतीय संस्कृति ब्लॉग अमेरिका और ईरान के संबंधों पर इतिहास की गहरी छाप है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच संबंध अविश्वास, प्रतिबंधों, परोक्ष संघर्षों और सैन्य टकरावों से प्रभावित रहे हैं। 2015 का संयुक्त व्यापक कार्ययोजना समझौता (जेसीपीओ) कूटनीति की सफलता माना गया था, लेकिन 2018 में अमेरिका के उससे बाहर निकलने के बाद ईरान ने यूरेनियम संवर्धन बढ़ाया और वाशिंगटन ने प्रतिबंधों को और सख्त किया। यही प्रक्रिया हालिया टकराव तक पहुंची। मौजूदा समझौते की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि परमाणु विवाद का मूल प्रश्न अभी भी अनसुलझा है। उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम का भंडार प्रमुख विवादों में शामिल है। अमेरिका संवर्धन क्षमता में कमी और कड़े अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण की मांग करता है, जबकि ईरान शांतिपूर्ण परमाणु संवर्धन को अपना संप्रभु अधिकार मानता है। अमेरिका के लिए ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अनिवार्य है, जबकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को राष्ट्रीय गौरव और रणनीतिक स्वतंत्रता से जोड़कर देखता है। क्षेत्रीय परिस्थितियां भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं हैं। इजराइल साफ कर चुका है कि उसकी सुरक्षा चिंताएं केवल अमेरिका–ईरान समझौते तक सीमित नहीं हैं। हिजबुल्लाह, ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव और उसकी मिसाइल क्षमताएं अब भी उसके लिए प्रमुख मुद्दे हैं। लेबनान में इजराइली सैन्य गतिविधियां इस समझौते के दायरे से बाहर हैं। दूसरी ओर हिजबुल्लाह और अन्य सहयोगी समूहों के साथ ईरान के संबंध भी मौजूदा व्यवस्था में शामिल नहीं हैं। इसलिए अमेरिका और ईरान के बीच संवाद जारी रहने के बावजूद क्षेत्रीय तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे। इसके बावजूद कुछ ऐसे कारण हैं जो इस समझौते को पिछले प्रयासों की तुलना में अधिक टिकाऊ बना सकते हैं। दोनों देशों ने प्रत्यक्ष संघर्ष की भारी कीमत चुकाई है। आर्थिक नुकसान, सैन्य खर्च और अंतरराष्ट्रीय दबाव ने संयम बरतने के लिए नई परिस्थितियां पैदा की हैं। साथ ही वार्ताकारों ने पहले संघर्ष रोकने और बाद में कठिन मुद्दों पर बातचीत करने की रणनीति अपनाई है। अंततरू इस समझौते को संकट का अंत नहीं, बल्कि एक लंबी और जटिल कूटनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। इसकी सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, भरोसेमंद सत्यापन व्यवस्था, परस्पर प्रतिबद्धताओं के पालन और क्षेत्रीय तनावों के प्रबंधन पर निर्भर करेगी। इसने युद्ध के तत्काल खतरे को कम किया है और क्षेत्रीय स्थिरता की उम्मीद जगाई है, लेकिन स्थायी शांति का रास्ता अभी भी लंबा है। दोनों देशों को दशकों पुराने अविश्वास से आगे बढ़कर यह साबित करना होगा कि बातचीत और समझौता निरंतर टकराव की तुलना में उनके राष्ट्रीय हितों के लिए अधिक लाभकारी हैं। तभी यह युद्धविराम स्थायी शांति में बदल सकेगा।

पंडित नेहरू के इंडिया से मोदी के भारत तक

हरदीप सिंह पुरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 जून को हमारे इतिहास के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। इस दरमियान काफी समय तक भारतीय शासन की सेवा करने के नाते मैं कह सकता हूं कि मोदीकी उपलब्धि कार्यकाल की लंबाई नहीं है। उन्होंने इस पद पर रहते हुए जो कुछ किया, वास्तविक उपलब्धि वह है। मोदी ने 10 जून, 2026 को प्रधानमंत्री के पद पर अपना लगातार 4399वां दिन पूरा कर लिया। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के 1952 में पहली निर्वाचित सरकार से 1964 में उनके निधन तक लगातार प्रधानमंत्री रहने के कीर्तिमान को पीछे छोड़ दिया। 1947 से देखें तो सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड अब भी पंडित नेहरू के नाम ही है। लेकिन मोदीने उन्हें हमारे गणराज्य के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित शासन प्रमुख रहने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इस दरमियान मैंने अपना कामकाजीवन शासन के अंदर गुजारा है। इस उपलब्धि में मेरी दिलचस्पी गणित के लिहाज से कम है। मेरी ज्यादा दिलचस्पी इसमें है कि इस उपलब्धि को कैसे मापा जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सिखाया है कि सरकार को इस बात से आंका जाना चाहिए कि कतार के आखिर में खड़े आदमी तक क्या कुछ पहुंचता है। इसे ही अंत्योदय कहते हैं। पंडित नेहरू के इंडियाच्य और मोदीके भारतच्य के बीच का फासला वह दूरी है जिसे इस आखिरी आदमी ने तय किया है। एक निष्पक्ष मूल्यांकन करें तो देखते हैं कि पंडित नेहरू को विरासत में क्या मिला था। उन्हें विरासत में एक ऐसा विभाजित उपमहाद्वीप मिला जो इतिहास के सबसे बड़े जबरन विस्थापन से जूझ रहा था, दो सदियों के औपनिवेशिक शोषण से खोखली हो चुकी अर्थव्यवस्था मिली, ऐसी आबादी मिली जिसमें पाँच में से एक से भी कम लोग पढ़–लिख सकते थे और औसत उम्र तीस साल के आस–पास थी। उस विरासत के आधार पर उन्होंने एक ऐसा संवैधानिक लोकतंत्र खड़ा किया जो टिका रहा, जबकि एक के बाद एक स्वतंत्र हुए कई अन्य देश सेना के जनरलों या तानाशाहों के कब्जे में चले गए। योजना आयोग दिशा तय करता था, सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर मजबूत पकड़ थी और लाइसेंस प्रणाली यह तय करती थी कि कौन क्या उत्पादन कर सकता है। विश्वविद्यालय, प्रयोगशालाएँ, परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रम – आजाद भारत की संस्थागत नींव उन्हीं वर्षों में रखी गई थी। मैं 1974 में विदेश सेवा में आया और जिस भारत का मैंने प्रतिनिधित्व किया, वह एक गंभीर देश था जिसने अपनी व्यवस्था की क्षमता के अनुसार पूरी गरिमा के साथ अभावों का सामना करने का रास्ता चुना था। उस व्यवस्था की कीमत तब तक साफ दिखने लगी थी जब तक मैं अपने करियर के मध्य पड़ाव पर पहुँचा। सरकार ने योजनाओं का आवंटन करना तो सीख लिया था, लेकिन वह वितरण करना नहीं सीख पायी थी। दिल्ली में घोषित किसी योजना और गाँव में मिलने वाले लाभ के बीच का जो फासला था, वहीं सारा पैसा गायब हो जाता था। एक पूर्व प्रधानमंत्री का यह मानना कि हर एक रुपये में से सिर्फ पंद्रह पैसे ही गरीबों तक पहुँच पाते हैं, इस मॉडल पर अपने आप में एक बड़ा सवाल था। सरकार योजना तो बना सकती थी, लेकिन वह लोगों तक पहुँच नहीं पाती थी। 2014 में मोदी को जो विरासत मिली, उसका भी उतना ही ईमानदार मूल्यांकन होना चाहिए। उन्होंने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कमान संभाली थी जिसे बाजार ने फ्रेजाइल फाइव (पांच सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं) की श्रेणी में रखा थाय जो अटकी हुई परियोजनाओं के बोझ तले दबी थी, दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार से घिरी थी जिसने शासन पर से जनता के भरोसे को ही खोखला कर दिया था। इसका समाधान उन्होंने एक बिल्कुल अलग तरह की व्यवस्था बनाकर किया। योजना आयोगच्य की जगह नीति आयोग ने ले ली, जो राज्यों को निर्देश देने के बजाय उन्हें साथ लेकर चलता है। पहचान (पहचान पत्र), बैंक खाता और मोबाइल फोन को एक साथ जोड़ा गया और सरकार ने बिचौलियों के बजाय, जो चार दशकों से अपना कमीशन ले रहे थे, नागरिकों को सीधे भुगतान करना शुरू कर दिया। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण एक निर्णायक माध्यम है जो बहुत साधारण लगता है लेकिन इसने शासन के इरादे की बजाय वास्तविक लाभ के मिलने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद जो हुआ, वह एक मंच के रूप में सरकार की नई परिकल्पना थी। भारत ने सार्वजनिक डिजिटल ढांचा और एक ऐसी पहचान व्यवस्था बनाई जो पूरे उपमहाद्वीप में काम करती है। एक ऐसा भुगतान नेटवर्क खड़ा किया गया जिसका आज पूरी दुनिया अध्ययन कर रही है। पचास करोड़ से अधिक जनधन खातों ने उन परिवारों के लिए औपचारिक बैंकिंग के दरवाजे खोल दिए,।

दलबदल का खेल और राजनैतिक ईमानदारी

विशाल

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उथल–पुथल दिखाई दे रही है। शिवसेना को एक बार फिर तोड़ने की खबरें हैं। जाहिर है यह टूट शिंदे गुट में नहीं, उद्धव ठाकरे गुट में करवाई जा रही है और इसके पीछे भी भाजपा का ही हाथ है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। कम से कम छह सांसदों के शिंदे गुट में जाने की खबरें हैं। सांसद संजय राउत ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि इन सांसदों को 15–15 करोड़ दिए गए हैं। यानी खुल कर खरीद–फरोख्त की बातें हो रही हैं। कुछ जगहों पर बाकायदा पोस्टर लगे हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे की तस्वीर के साथ ऑपरेशन टाइगर लिखा हुआ है, साथ ही लिखा है वेट एंड वॉच, यानी देखो और इंतजार करो। याद रहे कि कुछ दिनों से ऑपरेशन टाइगर शब्द महाराष्ट्र के राजनैतिक गलियारों में घूम रहा है।टाइगर यानी शेर बाला साहेब ठाकरे की खड़ी की हुई शिवसेना की पहचान रहा है। एकनाथ शिंदे खुद को बाल ठाकरे का असली उत्तराधिकारी बताते हुए शिवसेना के नाम और निशान पर तो कब्जा कर ही चुके हैं, अब ऑपरेशन टाइगर कहकर वे यह बताना चाह रहे हैं कि शिवसेना के असली शेर उनके साथ ही रहेंगे। वैसे ये अब शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के सोचने की बात है कि वे सर्कस में रिंग मास्टर के इशारों पर चलने वाले शेर को असली शेर मानते हैं या फिर जंगल में अपनी मर्जी से चलने वाले शेर को असली मानते हैं। शिवसेना का प्रतीक अब कौन सा शेर रहेगा, यह तो उसके कार्यकर्ता तय करेंगे। लेकिन इस देश की जनता को अब वाकई गंभीरता से सोचना होगा कि राजनैतिक दलों में टूट का जो सिलसिला नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से शुरु हुआ है, वो कहां जाकर थमेगा और तब तक क्या लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा।चार साल पहले जब शिवसेना को पहली बार तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भाजपा ने बिठाया था, तब इसे ऑपरेशन लोटस नाम दिया गया था। कर्नाटक, मध्यप्रदेश आदि में भी यही नाम चला, जबकि यह प्रकृति की एक अनुपम रचना कमल के फूल का अपमान था। भाजपा ने कमल के फूल को अपना प्रतीक चिह्न बनाया है, तो कम से कम उसकी विशेषता को अपनाने की कोशिश भी करती कि कीचड़ में खिलकर भी वह बेदाग रहता है और इस खूबसूरती के साथ खिलता है कि देवताओं के अर्पण के योग्य रहे। कमल जैसे सकारात्मक, सुंदर प्रतीक के साथ ऑपरेशन नाम जोड़कर उसके कोमल सौंदर्य पर आघात किया जाता है, जिसमें लोकतंत्र का भी अपमान होता है। किसी दल के विधायकों या सांसदों को लालच और दबाव बनाकर अपने दल में केवल इसलिए शामिल करना, ताकि सत्ता पर कब्जा किया जा सके, राजनैतिक भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण है। भाजपा यही उदाहरण बार–बार लगातार पेश कर रही है। राजनैतिक विश्लेषक और मीडिया के कई लोग इसे मास्टर स्ट्रोक बता कर भ्रष्टाचार को सही ठहराने में लगे हैं।युद्ध और प्रेम में सब जायज है, जैसे वाक्य अनैतिकता को बढ़ावा देने वालों ने अपनी सुविधा से गढ़े हैं, जिसे नकारना चाहिए। सही केवल वही है जो नैतिकता और कानून की कसौटी पर खरा उतरे। इस लिहाज से देखें तो भाजपा के चलाए दल–बदल ऑपरेशन सही नहीं हैं। अगर किसी की विचारधारा बदल जाए और फिर वह पार्टी बदले तो वह ठीक है। लेकिन आप किसी पार्टी और उसके चुनाव चिह्न पर लड़ते हैं, जीत हासिल करते हैं और कुछ वक्त के बाद धुरविरोधी पार्टी में चले जाते हैं तो यह सीधे–सीधे उस जनता के साथ धोखा है जिसने आपको जिताया। जैसे प.बंगाल में इस समय तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने एक अनजानी पार्टी एनसीपीआई में विलय का ऐलान किया, ताकि वे एनडीए का समर्थन कर सकें। ये 20 सांसद कम से कम एक करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2024 में इन लोगों को भाजपा के खिलाफ लड़ते हुए ही जीत मिली थी। अब ये सांसद भाजपा का विरोध नहीं करेंगे और इस तरह अपनी क्षेत्र की जनता के साथ धोखा करेंगे।2024 में भाजपा चार सौ पार का नारा दे रही थी ताकि संविधान बदल सके, इंडिया गठबंधन ने इसके खिलाफ लड़ने का ऐलान किया था और इसी वजह से भाजपा को 240 सीटों पर रुकना पड़ा था। तब संविधान पर आया खतरा कुछ वक्त के लिए टल गया था। लेकिन अब भाजपा ने उस खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। संसद में इंडिया गठबंधन के सांसदों को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार को यह समझ आ गया है कि अभी जो बहुमत उसके पास है, उसमें मनमर्जी नहीं की जा सकती है। बीते 17 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में संविधान संशोधन विधेयक सरकार इंडिया ब्लॉक की एकजुटता के कारण ही पारित नहीं करवा पाई थी। इसके बाद बंगाल में उसकी जीत तो हो गई, लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन में आपसी मजबूती भी बढ़ी। क्योंकि सभी दलों को यह समझ आ गया कि भाजपा अब विपक्ष को किसी हाल में चुनाव नहीं जीतने देगी। भाजपा इंडिया गठबंधन में दरार नहीं डाल पा रही है तो अब उसके दलों को तोड़ने में लगी है। टीएमसी में उसे काफी हद तक सफलता मिल गई है। लेकिन संसद में एकाधिकार के लिए उसे और संख्याबल चाहिए, तो अब फिर से शिवसेना निशाने पर है। भारतीय संस्कृति ब्लॉग हालांकि शिवसेना

(यूबीटी) ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपकर मांग की है कि शिवसेना (यूबीटी) को ही संसद में एकमात्र आधिकारिक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाती रहे। किसी भी अलग गुट, बागी गुट या स्वतंत्र समूह को कोई पहचान, दर्जा, सुविधा या विशेषाधिकार न दिया जाए। पत्र में यह भी लिखा है कि ऐसी किसी भी मांग पर फैसला लेने से पहले उद्धव ठाकरे गुट को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह संविधान की दसवीं अनुसूची (दल–बदल विरोधी कानून) के तहत उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। अब ओम बिड़ला क्या फैसला लेते हैं यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन दलबदल के लगातार हो रहे प्रकरणों में यह विचारणीय है कि आखिर भाजपा को ऐसा करने का मौका क्या राजनैतिक दलों के नेता खुद नहीं दे रहे हैं। राजनीति में जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है, उस में जांच एजेंसियों के सियासी इस्तेमाल की गुंजाइश बढ़ गई है। जैसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक एमएलसी राज्यसभा सांसद भाजपा ने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा? क्या लालच रहा होगा? क्या डर रहा होगा? स्वार्थ, लालच और डर ही वे कारक हैं, जिनके बूते दल–बदल संभव हो पा रहा है। आज भाजपा यह कर रही है, मुमकिन है कल कोई दूसरा सत्ताधारी दल यही करे।

ओपी राजभर की पोस्ट ने सपा में मचाई खलबली, लिखा- टूट होकर रहेगी

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी में समाजवादी पार्टी क्या टूटने जा रही है? बीते कुछ समय से भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेता लगातार सपा में टूट की बात कह रहे हैं। इसी बीच सुभासपा अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने एक्स पर पोस्ट करके सरगर्मी और बढ़ा दी है। उन्होंने लिखा कि, श्कल

से सब पूछ रहे हो कि सपा में क्या टूट होने वाली है? तो सुनो! सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की श्बागी भूमिश का एक लाल करेगा। और करे भी क्यों न? इतना ही नहीं उन्होंने आगे लिखा कि, श्कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे श्बागी बलियाश का लाल बहुत आहत है। योजना पहले से थी, लेकिन कल की घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया। उन्होंने दावा किया कि टूट होकर रहेगी। अपनी पोस्ट में मंत्री ने आगे लिखा कि, श्मेरी एक प्रतिक्रिया पर जिस तरह से पूरा सैफई खानदान मुझे गाली देने और सफाई देने में जुट गया है, उससे ज्यादा बेहतर है कि अखिलेश बाबू ट्विटर और पीसी वाली नेतागिरी छोड़कर अब सांसद बचाओ अभियान शुरू कर दें। दुखी एवं निराश सांसदों के घर जाकर उनसे माफी मांगें।

जनता तो जनता डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी परेशान, घर में भरा नाले का गंदा पानी

लखनऊ, (संवाददाता)। राजध ानी लखनऊ में बारिश से पहले ही नाला चोक होने के कारण पिछले पांच दिन में दो बार उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास के अंदर गंदा पानी भर चुका है। शिकायत के बाद भी समस्या का पूरी तरह निदान न होने से वह नाराज हैं। इस बाबत उनके कार्यालय ने पत्र लिखकर कड़ी नाराजगी जताई है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद का आवास सात कालिदास मार्ग है। पिछले एक सप्ताह में यहां कई बार नाले का पानी घर के अंदर लॉन में भर चुका है। 12 जून को जब पानी भरा था तो नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और पानी निकालकर चली आई थी। टीम ने ये भी कहा था कि अगले दिन आकर वह समस्या का स्थायी निदान करेंगे। मंगलवार को फिर लॉन में गंदा पानी भर गया। इससे उपमुख्यमंत्री बहुत नाराज हुए। उनके निजी सचिव ने नगर आयुक्त को पत्र भेजकर कहा है कि उपमुख्यमंत्री के आवास के अंदर सीवर–नाले का पानी आ रहा है। इस बारे में निगम के जनसंपर्क अधिकारी को अवगत कराया गया था। आवास पर निरीक्षण के लिए जेई प्रतिमा यादव एवं किशोरी लाल पहुंचे थे। दोनों ने आश्वासन दिया कि अगले दिन समस्या का समाधान करा दिया जाएगा, लेकिन समाधान हुआ नहीं। गंदा पानी फिर आवास के अंदर जमा हो गया है। ऐसे में समस्या दूर कराने में लापरवाही करने वाले संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जानकारों ने बताया इन अधिशासी अभियंता अतुल मिश्रा अवकाश पर हैं और सहायक अभियंता अवधेश सिंह ड्यूटी पर हैं। उनको वहां पर जाना चाहिए था मगर वह मौके पर नहीं गए। यदि वह जाते तो समस्या दूर हो जाती।

संक्षिप्त खबरें

लाइसेंसी बंदूक छीनकर फरार हुआ युवक गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। गोमतीनगर विस्तार थाना पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक छीनकर फरार होने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से छीना गया शस्त्र बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अतिरिक्त धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया है।पुलिस के अनुसार पाम रेजीडेंसी, बक्काश निवासी रजनीश सिंह ने 14 जून 2026 को थाना गोमतीनगर विस्तार में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक युवक उनकी लाइसेंसी 12 बोर डबल बैरल बंदूक छीनकर फरार हो गया है। पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम को आरोपी की तलाश में लगाया गया। मोबाइल नंबर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सुरागरसी और पतारसी करते हुए आरोपी की पहचान की। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर बुधवार तड़के पुलिस टीम ने शहीद पथ के किनारे रेलवे लाइन सर्विस रोड स्थित झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपी की पहचान श्रेयस वशिष्ठ उर्फ मानस सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम बीकामऊ खुर्द, थाना बीकेटी तथा वर्तमान निवासी जानकीपुरम गार्डन, थाना गुडम्बा, लखनऊ के रूप में हुई है। आरोपी की उम्र लगभग 22 वर्ष बताई गई है।

प्रवक्ता भर्ती साक्षात्कार में फर्जीवाड़े का प्रयास नाकाम

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रवक्ता भर्ती साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से चयन प्रक्रिया में शामिल होने के प्रयास का बड़ा खुलासा करते हुए एक महिला अभ्यर्थी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। आयोग ने मामले को भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और गोपनीयता को प्रभावित करने का गंभीर प्रयास बताते हुए संबंधित अभ्यर्थी को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है।आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार विज्ञापन संख्या 02ध्2022 के अंतर्गत प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार 15 जून से 27 जून 2026 तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित किए जा रहे हैं। बुधवार को प्रथम पाली के साक्षात्कार के दौरान रसायन विज्ञान विषय की एक महिला अभ्यर्थी आयोग कार्यालय पहुंची और दावा किया कि वह लिखित परीक्षा में सफल घोषित हुई है, लेकिन तकनीकी कारणों से उसका साक्षात्कार पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा है।महिला अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बाद आयोग ने उसके दावे की जांच शुरू की। कार्यालयीय अभिलेखों और परीक्षा संबंधी रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर पता चला कि संबंधित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल नहीं हुई थी। जांच में यह भी सामने आया कि उसने आयोग द्वारा जारी अपने मूल प्रवेश–पत्र में कूटरचना कर एक अन्य सफल अभ्यर्थी का अनुक्रमांक दर्ज कर दिया था और उसी आधार पर साक्षात्कार में शामिल होने का दावा कर रही थी।आयोग ने इसे चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने और अनुचित लाभ प्राप्त करने का सुनियोजित प्रयास मानते हुए तत्काल कार्रवाई की। फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने के आरोप में संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई तथा उसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया।

सीएम ग्रिड योजना में 442 करोड़ से संवरेंगी शहर की सात और सड़कें

लखनऊ, (संवाददाता)। सीएम ग्रिड योजना के तहत शहर में अब सात और सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। ये सड़क योजना के चौथे चरण में शामिल की जा रही हैं। बृहस्पतिवार को शासन स्तर पर विशेष बैठक होनी है जिसमें चौथे चरण में बनने वाली सड़कों के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। करीब दो वर्ष पहले शासन ने सीएम ग्रिड योजना शुरू की थी। इसके पहले चरण में शहर की सात सड़कों को शामिल किया गया था। इनका निर्माण 186 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इन सड़कों का काम जनवरी में ही पूरा होना था जो अब तक चल ही रहा है। करीब 20 प्रतिशत काम बचा है। दूसरे चरण में तीन सड़कों का निर्माण करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। तीसरे चरण में भी काम चल रहा है। अब चौथा चरण शुरू होने वाला है। इसके लिए नगर निगम की ओर से अभी अलग–अलग इलाकों की सात सड़कों को चुना गया है। इनके निर्माण पर करीब 442 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चौथे चरण के प्रस्ताव में शामिल सड़कों में कितनी बनेंगी या सभी बनेंगी, यह बृहस्पतिवार को होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में तय होगा। वृंदावन योजना स्थित सेक्टर–6 में आकाश एनक्लेव के सामने स्थित पेट्रोल पंप तिराहे से परशुराम चौराहा होते हुए ऐलन हाउस स्कूल व रमजान नगर चौराहा तक। हिंद नगर वार्ड व विद्यावती द्वितीय वार्ड स्थित लोकबंधु चौराहे से पराग रोड होते हुए पुरानी चुंगी व सीएमएस से रोहतास अपार्टमेंट व कानपुर रोड तक। सीएमएस से कमेटी हॉल व गंगाराम हॉस्पिटल होते हुए।

लंबित भुगतान मामलों के निस्तारण को कौशल विकास मिशन का अंतिम अवसर

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने विभिन्न पूर्व संचालित कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत लंबित भुगतान संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं एवं जनपदीय अधिकारियों को अंतिम अवसर प्रदान किया है। मिशन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने पर संबंधित दावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें अपात्र मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।मिशन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पूर्व में संचालित विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत ऐसे अनेक प्रकरण लंबित हैं, जिनमें प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण व्यय से संबंधित दावा, बीजक, सत्यापन आख्या अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेज अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इन लंबित मामलों के समाधान के लिए संबंधित प्रशिक्षण प्रदाताओं और जिला स्तरीय अधिकारियों को सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर सभी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।कौशल विकास मिशन ने कहा है कि प्राप्त अभिलेखों का परीक्षण किए जाने के बाद नियमानुसार भुगतान संबंधी कार्रवाई की जाएगी, ताकि पात्र प्रशिक्षण संस्थाओं एवं लाभार्थियों को देय भुगतान का निस्तारण किया जा सके। मिशन का उद्देश्य लंबे समय से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान कर योजनाओं से जुड़ी वित्तीय प्रक्रियाओं को पूर्ण करना है।अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अवसर अंतिम होगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी दावे, क्लेम या अभिलेख पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों को अपात्र मानते हुए संबंधित योजनाओं के समापन की कार्रवाई तथा अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रक्रियाएं नियमानुसार पूरी की जाएंगी।मिशन ने सभी संबंधित प्रशिक्षण प्रदाताओं, संस्थाओं और जनपदीय अधिकारियों से समयसीमा का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण से कौशल विकास योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को और मजबूती मिलेगी तथा वित्तीय दायित्वों का समयबद्ध निर्वहन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

संक्षिप्त खबरें

लखनऊ को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का इंजन बनाने पर जोर

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा जनपद लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में राजधानी लखनऊ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र तथा आधारभूत संरचना के विकास को नई गति देते हुए सभी विभाग अपने लक्ष्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करें। वह बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनपद की आर्थिक प्रगति, विकास योजनाओं और कानून–व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार लखनऊ की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपये है तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जनपद का योगदान 5.56 प्रतिशत है। वर्ष 2024–25 में सेवा क्षेत्र का योगदान 62.76 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र का 30.14 प्रतिशत तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का 7.10 प्रतिशत दर्ज किया गया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इन तीनों क्षेत्रों में संतुलित और तेज विकास सुनिश्चित कर लखनऊ को प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाए।कृषि क्षेत्र की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2.70 लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित किए जाने और 54.16 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि हस्तांतरित किए जाने की जानकारी दी गई। मंत्री ने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 36,562 किसानों के बीमित होने की जानकारी पर उन्होंने किसानों को अधिकाधिक योजना से जोड़ने तथा दावों के त्वरित निस्तारण के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।बैठक में बताया गया कि जनपद में अब तक 54 कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) गठित किए जा चुके हैं।

हथकरघा उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक तकनीक, बेहतर विपणन व्यवस्था और प्रभावी योजनाओं के माध्यम से नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग क्षेत्र केवल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक नहीं है, बल्कि लाखों बुनकर परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार भी है। इसलिए विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।मंगलवार को विधान भवन स्थित सभा कक्ष संख्या–80 में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, यूपिका तथा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं, उत्पादन, विपणन, वित्तीय स्थिति तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, निगमों के संचालन और बुनकर कल्याण कार्यक्रमों को लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई।समीक्षा के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग की सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए।

सड़ी–गली सामग्री से बन रहे थे अचार, सॉस और जैम, छापे में कारखानों का हाल देख दंग रह गई टीम

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेशव्यापी विशेष अभियान चलाया। 15 और 16 जून को फल–सब्जी उत्पादों से बनने वाले खाद्य पदार्थों की इकाइयों का निरीक्षण हुआ। इस दौरान मानकों का उल्लंघन और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां सामने आईं। मानकों को ताक पर रखकर अचार, सॉस, जैम, जेली व चटनी आदि बनाया जा रहा था। विभाग की टीम ने दो दिन में 337 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। कुल 550 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कई स्थानों पर सड़ी–गली सामग्री और रसायन का प्रयोग पाया गया। अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा मानकों, स्वच्छता और कच्चे माल की गुणवत्ता जांची। 195.5 क्विंटल खाद्य पदार्थ जब्त किया गया, जिसका मूल्य करीब 17.06 लाख रुपये है। मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त 171.8 क्विंटल खाद्य पदार्थ नष्ट किया गया। इसका अनुमानित मूल्य करीब 11.86 लाख रुपये है। छोटे खुदरा विक्रेताओं को इस अभियान से बाहर रखा गया। लखनऊ में मुंबई फूड इंडस्ट्रीज से 458 किलोग्राम सॉस सीज हुआ। बाबा फूड प्रोडक्ट्स बिना लाइसेंस संचालित पाया गया, जिसे बंद कराया गया।

फर्जी दस्तावेज के सहारे साक्षात्कार में शामिल होने की कोशिश नाकाम

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रवक्ता भर्ती साक्षात्कार के दौरान फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से चयन प्रक्रिया में शामिल होने का एक मामला सामने आया है। आयोग की सतर्कता से एक महिला अभ्यर्थी की कथित जालसाजी का खुलासा हुआ, जिसके बाद उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसे स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 02ध्2022 के अंतर्गत प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार 15 जून से 27 जून 2026 तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को प्रथम पाली के दौरान रसायन विज्ञान विषय की एक महिला अभ्यर्थी आयोग कार्यालय पहुंची और प्रार्थना पत्र देकर दावा किया कि वह लिखित परीक्षा में सफल हुई है, लेकिन उसका साक्षात्कार पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा है।अभ्यर्थी के दावे को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा कार्यालयीय अभिलेखों और संबंधित दस्तावेजों की जांच कराई गई। जांच में सामने आया कि महिला अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण ही नहीं हुई थी। आरोप है कि उसने आयोग द्वारा जारी अपने प्रवेश–पत्र में कूटरचना करते हुए रसायन विज्ञान विषय के किसी सफल अभ्यर्थी का अनुक्रमांक अंकित कर साक्षात्कार में शामिल होने का अनुचित प्रयास किया।आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा फर्जी एवं कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत कर आयोग की गोपनीयता, पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया की शुचिता को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई तथा तत्काल स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया।उन्होंने कहा कि आयोग परीक्षा और साक्षात्कार प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, जालसाजी या अनुचित साधनों के प्रयोग को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे किसी भी प्रकार के कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग न करें और न ही ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं के संपर्क में आएं जो उन्हें अवैध तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करते हों। आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की अवांछनीय और गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।इस घटना के बाद आयोग ने एक बार फिर चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

यासीनगंज में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

लखनऊ, (संवाददाता)। सआदतगंज थाना क्षेत्र के यासीनगंज स्थित बड़ी शाही मस्जिद के निकट एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।पुलिस के अनुसार बुधवार 17 जून 2026 को डायल–112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बड़ी शाही मस्जिद के पास एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर थाना सआदतगंज पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और जांच–पड़ताल की।प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान विनीश यादव (31 वर्ष) पुत्र शंकर लाल यादव निवासी 432ध्32 कैम्पवेल रोड, बड़ी शाही मस्जिद के निकट, यासीनगंज, थाना सआदतगंज के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, जिससे मृत्यु के कारणों की पुष्टि हो सके।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इंडिया–अफगानिस्तान मैच को लेकर लखनऊ में अभेद्य सुरक्षा कवच

लखनऊ, (संवाददाता)। भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले अंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेट मैच को लेकर राजधानी लखनऊ में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस मुकाबले के लिए लखनऊ पुलिस ने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करते हुए पूरे आयोजन क्षेत्र को सुपर जोन, जोन, सेक्टर और सब–सेक्टर में विभाजित किया है। पुलिस प्रशासन का दावा है कि मैच के दौरान सुरक्षा, यातायात, भीड़ प्रबंधन और वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार स्टेडियम और उसके आसपास के क्षेत्र को चार सुपर जोन, छह जोन, 16 सेक्टर और 36 सब–सेक्टर में विभाजित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए तीन पुलिस उपायुक्त, पांच अपर पुलिस उपायुक्त और 11 सहायक पुलिस आयुक्त तैनात किए गए हैं। इनके अलावा 42 निरीक्षक, 178 उपनिरीक्षक, 30 महिला उपनिरीक्षक तथा 376 मुख्य आरक्षी और आरक्षी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे।महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर 158 महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या अवांछित गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।यातायात व्यवस्था को भी विशेष रूप से सुदृढ़ बनाया गया है। इसके लिए एक सुपर जोन, तीन जोन, आठ सेक्टर और 19 सब–सेक्टर बनाए गए हैं। यातायात प्रबंधन में एक पुलिस उपायुक्त, तीन अपर पुलिस उपायुक्त, आठ सहायक पुलिस आयुक्त, 32 निरीक्षक, 200 उपनिरीक्षक, 525 पुलिसकर्मी और 84 होमगार्ड लगाए गए हैं। मैच के दौरान प्रमुख मार्गों पर विशेष यातायात डायवर्जन योजना लागू रहेगी तथा वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की गई है ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए छह कंपनियां पीएसी, वायरलेस यूनिट, स्थानीय अभिसूचना इकाई, एटीएस टीम, बम निरोधक एवं निस्तारण दस्ता, एंटी–माइन टीम तथा अन्य विशेष जांच दल भी तैनात किए गए हैं।

सूचना देने में लापरवाही पर बीएसए अलीगढ़ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

लखनऊ, (संवाददाता)। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों की अनदेखी और आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने पर राज्य सूचना आयोग ने अलीगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।मामला शिकायतकर्ता मोहम्मद शोएब द्वारा दायर शिकायत से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने 17 दिसंबर 2024 को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित नर्सरी विद्यालयों से जुड़ी विभिन्न सूचनाएं मांगी थीं। निर्धारित समयावधि के भीतर सूचना उपलब्ध न कराए जाने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया और शिकायत दर्ज कराई। प्रकरण की सुनवाई के दौरान आयोग ने संबंधित जनसूचना अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ को कई बार नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने और आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इसके बावजूद न तो आयोग के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की गई और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। आयोग ने इसे सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की गंभीर अवहेलना माना।सुनवाई में यह तथ्य भी सामने आया कि शिकायतकर्ता को उसके आवेदन के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी। आयोग ने पाया कि संबंधित जनसूचना अधिकारी ने अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और आयोग द्वारा जारी नोटिसों की भी लगातार उपेक्षा की।इन परिस्थितियों को गंभीर मानते हुए।

समर एडवेंचर कैंप 2026 के अंतर्गत बच्चों ने स्वच्छता, सेवा एवं सामाजिक जागरूकता का दिया संदेश

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

फतेहगढ़। द सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर, फतेहगढ़ द्वारा आयोजित समर एडवेंचर कैंप 2026 के अंतर्गत सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 40 बच्चों ने स्वच्छता अभियान, जन–जागरूकता गतिविधियों, वृद्धाश्रम भ्रमण तथा ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, फतेहगढ़ का दौरा कर सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सेवा भावना का उत्कृष्ट परिचय दिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। बच्चों ने स्थानीय दुकानदारों एवं क्षेत्रवासियों को स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जागरूकता पम्पलेट वितरित किए तथा उन्हें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इस पहल को स्थानीय नागरिकों द्वारा सराहा गया। इसके पश्चात बच्चों ने मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद स्थित वृद्धाश्रम का भ्रमण किया, जहाँ उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के साथ समय बिताया तथा उनसे आत्मीय संवाद स्थापित किया। बच्चों ने बुजुर्गों के अनुभवों से सीख प्राप्त की और उनके प्रति सम्मान, संवेदनशीलता एवं करुणा का भाव व्यक्त किया। वृद्धजनों ने भी बच्चों के इस स्नेहपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों ने ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, फतेहगढ़ का भी दौरा किया। वहाँ उन्हें पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों ने नर्सिंग स्टाफ एवं चिकित्सा कर्मियों की सहायता करते हुए पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों के प्रति सेवा और सम्मान का भाव प्रदर्शित किया। इस दौरान उन्हें राष्ट्र की रक्षा में योगदान देने वाले वीर सैनिकों और उनके परिवारों की देखभाल के महत्व से भी अवगत कराया गया। श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों ने छबील सेवा का आयोजन कर राहगीरों एवं स्थानीय नागरिकों को शीतल पेय वितरित किया। इस सेवा गतिविधि के माध्यम से बच्चों ने निस्वार्थ सेवा, मानवता एवं परोपकार के सिख मूल्यों को आत्मसात किया। यह कार्यक्रम बच्चों में अनुशासन, सामाजिक जागरूकता, सहानुभूति, सेवा भावना तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने की दिशा में एक प्रेरणादायक एवं सार्थक पहल सिद्ध हुआ।

भिवंडी में चिकन पिज्जा खाने से 14 लोग बीमार, फूड प्वाइजनिंग की आशंका

ब्यूरो रिपोर्ट धनन्जय विश्वकर्मा, मुंबई ब्यूरो चीफ

दैनिक देश की उपासना समाचार पत्र भिवंडी, महाराष्ट्र। भिवंडी शहर में कथित रूप से चिकन पिज्जा खाने के बाद 14 लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है। सभी प्रभावित लोगों को उल्टी, पेट दर्द और दस्त की शिकायत होने पर तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी पीड़ितों ने एक स्थानीय फूड आउटलेट से चिकन पिज्जा मंगवाकर उसका सेवन किया था। भोजन करने के कुछ घंटों बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने संबंधित प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर

प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिए हैं। प्रारंभिक तौर पर फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई जा रही है, हालांकि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बीमारी के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। अस्पताल सूत्रों के अनुसार सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशासन ने नागरिकों से बाहर का भोजन करते समय सावधानी बरतने तथा किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की शिकायत तुरंत संबंधित विभाग को देने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

महिलाओ से लूट,छेड़खानी,चेन स्नैचिंग की घटनाओं मे बढ़ोतरी

अयोध्या। इस समय एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता के लिए संबंधित थानों के प्रभारी निरीक्षक तथा इस टीम मे गठित महिला प्रभारी व उनकी टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है।वहीं दूसरी ओर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं से छेड़खानी,चेन स्नैचिंग और लूट की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं।आए दिन शाम होते ही शहर के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बेटियों के साथ इस तरह की अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं।देखा जाए तो पिछले सप्ताह कोतवाली नगर क्षेत्र के देवकाली पुलिस चौकी क्षेत्र में देर रात एक महिला के साथ चेन स्नेचिंग की घटना हुई वहीं पिछले दिनों थाना हैदरगंज क्षेत्र मे एक महिला के साथ छेड़खानी की वारदात सामने आई।कोतवाली नगर के अलावा थाना कैंट क्षेत्र,बीकापुर, पूरा कलंदर सहित कई ऐसे थाना क्षेत्र है। जहां पर इस तरह की घटना घटी।थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में पिछले दिनों बेटी के साथ दुराचार की घटना सामने आयी। स्थानीय थानों पर फरियाद न सुने जाने पर पीड़ित महिलाएं सीधे एसएसपी कार्यालय आकर अपनी दुखड़ा सुनती हैं। जबकि प्रतिदिन शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं तथा बेटियों को जागरूक किया जाता है लेकिन यह सिर्फ एक कागजी कार्यवाही तक ही सिमट कर रह गया है।अभी पिछले सप्ताह कोतवाली नगर क्षेत्र के देवकाली पुलिस चौकी के समीप एक महिला से हुई चौन लूट में सीसीटीवी फुटेज खगांल कर नगर पुलिस ने यह दावा भी किया कि आरोपी से शीघ्र ही गिरफ्त में होंगे लेकिन मामला ठंडा बस्ते में ही चला गया इसी तरह कई ऐसे थाना क्षेत्र में घटनाएं घटी लेकिन वारदात को करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए।इस समय बीकापुर कोतवाली मे बहुचर्चित एक मामला पवन देव जी का भी सामने आ रहा है पहले तो पुलिस उसे काफी दबानी चाहिए लेकिन पीड़िता के अथक प्रयास के बाद यह मामला एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के सामने आया तो उन्होंने उक्त आरोपी को पकड़ने के लिए न सिर्फ वहां के प्रभारी निरीक्षक को हटा दिया बल्कि नवागत प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र पाण्डेय को आरोपी पवन देव को गिरफ्तार करने का सख्त निर्देश दिया।साथ ही साथ घ15000 का इनाम रखा।जिले मे कुछ घटनाएं ऐसी भी है जो दब गई है लेकिन जनता पुलिस से एक ही सवाल पूछती है किमिशनक्ष शक्ति अभियान से क्या मतलब जब महिला और बहू बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। क्या पेंपलेट पोस्ट से ही काम चल जाएगा।

नेतृत्व कमजोर होने पर जनप्रतिनिधि नए विकल्प तलाशते हैं : संजय निरुपम

देश की उपासना समाचार पत्र

मुंबई। शिवसेना (शिंदे गुट) के उपनेता संजय निरुपम ने शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों में कथित असंतोष और अलग समूह बनाए जाने की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह किसी राजनीतिक साजिश का परिणाम नहीं, बल्कि नेतृत्व के प्रति बढ़ते असंतोष का संकेत है। गुरुवार को आयोजित पत्रकार परिषद में संजय निरुपम ने कहा कि संसद की कार्यवाही से संबंधित व्हिप का अपना संवैधानिक और कानूनी दायरा होता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में जिस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, उसका कोई ठोस कानूनी आधार नजर नहीं आता। उन्होंने राजनीतिक दलों से तथ्यों और संसदीय प्रक्रियाओं के आधार पर चर्चा करने की अपील की। निरुपम ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में जब सांसद, विधायक और पदाधिकारी लगातार पार्टी छोड़ने लगते हैं, तो यह संगठन और नेतृत्व के लिए गंभीर चिंता का विषय होता है। उनके अनुसार वर्ष 2022 के बाद से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उद्धव

ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को छोड़कर शिवसेना (शिंदे गुट) से जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने सांसद संजय रावत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके बयान अक्सर आक्रामक और विरोधाभासी होते हैं। निरुपम ने कहा कि जिन सांसदों की कुछ समय पहले तक प्रशंसा की जा रही थी, आज उन्हीं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। उन्होंने वर्ष 2022 के महाराष्ट्र राजनीतिक घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी कई प्रकार की चेतावनियां और दावे किए गए थे, लेकिन बाद की परिस्थितियों ने उन दावों को गलत साबित कर दिया। निरुपम ने कहा कि लोकतंत्र में धमकी और भय की राजनीति की नहीं, बल्कि जनसमर्थन, संगठनात्मक क्षमता और जनता के विश्वास की अहम भूमिका होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनप्रतिनिधि अपने राजनीतिक भविष्य और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही प्रक्रिया राजनीतिक दलों की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करती है।

कथा वाचक पवन देव को पकड़ने के लिए पुलिस और

अयोध्या। दुष्कर्म के आरोपी कथावाचक पवन देव जी महाराज के ऊपर पुलिस द्वारा इनाम घोषित करने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। गिरफ्तारी के लिए अयोध्या पुलिस और क्राइम ब्रांच एसओजी टीम अयोध्या के अलावा अन्य संभावित ठिकानों पर तलाश में जुटी हुई है। दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहे 15,000 रुपये के इनामी कथावाचक पवन देव महाराज की तलाश में एसओजी टीम द्वारा बृहस्पतिवार को गोंडा जनपद के मनकापुर में छापेमारी की गई। गुरुवार को मनकापुर कोतवाली पुलिस के सहयोग से एसओजी द्वारा मनकापुर थाना क्षेत्र के बैरीपुर रामनाथ गांव में छापेमारी की गई। पुलिस टीम ने गांव निवासी इंद्र कुमार तिवारी उर्फ रामायण के घर पर छापा मारा, जो खुद को आचार्य रामायण शांडिल्य बताते हैं। इंद्र कुमार तिवारी ने कथावाचक पवन देव जी महाराज के विरुद्ध बीकापुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद फेसबुक पर पोस्ट कर पवन देव महाराज का समर्थन किया था। अयोध्या पुलिस को संदेह था कि पवन देव महाराज इंद्र कुमार तिवारी के घर पर छिपे हो सकते हैं। हालांकि, छापेमारी के दौरान न तो पवन देव महाराज मिले और न ही इंद्र कुमार तिवारी अपने घर पर मौजूद थे। पुलिस टीम ने इंद्र कुमार तिवारी के घर तलाश करने के साथ उनकी कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। मनकापुर कोतवाल गौरव सिंह तोमर के अनुसार अयोध्या एसओजी टीम को आशंका थी कि पवन देव महाराज उनके थाना क्षेत्र में छिपे हो सकते हैं। उन्होंने अयोध्या पुलिस को पूरा सहयोग देने की बात कही। छापेमारी के बाद पुलिस टीम वापस अयोध्या लौट गई। प्रसिद्ध कथा वाचक पवन देव महाराज पर सिवान बिहार निवासी एक महिला ने शादी का झांसा देखकर के दुष्कर्म करने, धोखा देने, लाखों रुपए के जेवरात हड़पने, एवं मारपीट का आरोप लगा करके बीकापुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराया है। कथावाचक के पिता पंडित रमाकांत शास्त्री को भी आरोपी बनाया गया है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पवन देव महाराज फरार चल रहे हैं। मलेथूकनक स्थित घर में ताला लगा हुआ है। जिनकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी द्वारा 15000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है।इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र पांडेय ने बताया कि पुलिस शीघ्र गिरफ्तारी के लेगी'

ट्रेन की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल,दोनों पैर कटे,हालत नाजुक

, सुल्तानपुर। लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के लम्भुआ–दुर्गापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास गुरुवार शाम एक अज्ञात व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रेन ड्राइवर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी लम्भुआ पहुंचाया। घायल के दोनों पैर कट गए हैं और पेट पर भी चोटें हैं। प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल में रिफर कर दिया गया। घायल ने अपना नाम संतोष तिवारी पुत्र विष्णु नारायण तिवारी, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी लाल बंगला कानपुर बताया है। उसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ है। रेलवे पुलिस व लम्भुआ पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो भी परिजन व जानने वाले हों, वे जिला अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं।

महिला उप निरीक्षक प्रिया ने सभी कर्मियों के साथ किया योगाभ्यास

अयोध्या।महिला थाना परिसर मे प्रतिदिन महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला की अध्यक्षता मे महिला कर्मी योग कर रही है।इसी कडी मे गुरुवार को महिला उप निरीक्षक प्रिया ने महिला थाना परिसर मे तैनात सभी महिला पुलिस कर्मियों के साथ योगा अभ्यास किया।उन्होंने बताया महिला परिसर मे यह योगाभ्यास 21 जून तक चलता रहेगा।इस मौके पर उनके

अलावा महिला उप निरीक्षक सोनी, प्रिया, श्वेता राठौर, सहित विमलेश,सायरा बानू,करिश्मा दूबे,वंदना, प्रेया सहित अन्य महिला पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

शिक्षक के घर लाखों की चोरी

ब्यूरो चीफ आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुल्तानपुर। कोतवाली देहात क्षेत्र के मनिकापुर गांव में अज्ञात चोरों ने शिक्षक अमर बहादुर वर्मा के घर छत का जाल काटकर धावा बोल दिया। चोर आलमारी में रखे लाखों रुपये के सोने–चांदी के जेवरात और कीमती सामान समेट ले गए। अमर बहादुर वर्मा प्राथमिक विद्यालय शिवगढ़, लंभुआ में तैनात हैं। खास बात यह है कि उनकी बेटी की विदाई शनिवार को होनी थी और परिवार तैयारियों में जुटा था। सुबह चोरी की जानकारी होने पर घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है।

सीएम योगी पहुचे जैन मंदिर जहाँ मनाया जा रहा है जैन समाज का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।सीएम योगी जैन मंदिर पहुंचे जहाँ पर जैन समाज का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 3रू40 बजे श्री ऋषभ देव दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए है।जैन धर्म में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का विशेष महत्व है। यह आयोजन तीर्थंकरों के जीवन से जुड़े पांच प्रमुख कल्याणकों, गर्भ, जन्म, तप, केवलज्ञान और मोक्ष की स्मृति में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से आए जैन श्रद्धालु, संत और धर्माचार्य मौजूद

है। अयोध्या का जैन धर्म से भी गहरा संबंध माना जाता है। सीएम योगी योगी की उपस्थिति इस कार्यक्रम को और अधिक महत्वपूर्ण बना रही है।राममंदिर चढ़ावा चोरी पर योगी बोले कि अपराधी कोई हो, नहीं बचेगा।15 दिन में इस मामले की जाँच कर रही एसआईटी टीम दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी।योगी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा के दोहरे चरित्र को देखो, कहते हैं राम भक्तों का अपमान हुआ है।कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले और राम के नारे लगाने पर गोली चलवाने वाले लोग उपदेश देने चले हैं। अयोध्या के बारे में समाचार पत्रों से सुनने को मिला। हमने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बैठाई। एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। लेकिन, मैं सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी अनर्गल टिप्पणी न करें, जो रामभक्तों को आहत करे।

'राजकीय बाल सुधार गृह में गूंजा योग का संदेश, सखी वन स्टॉफ ने बालिकाओं को किया जागरूक'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहाँपुर' अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस–2026 के उपलक्ष्य में आयोजित योग सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय बाल सुधार गृह में योग शिविर का आयोजन किया गया। पुराना जिला चिकित्सालय नगर के मुख्य योग प्रशिक्षक मृदुल कुमार गुप्ता द्वारा कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया गया। उन्होंने बच्चों को योग के महत्व से अवगत कराते हुए नियमित योगाभ्यास को स्वस्थ एवं अनुशासित जीवन का आधार बताया तथा इसे दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान संस्थान में निवासरत बालिकाओं को भी योग के प्रति जागरूक किया गया। सखी वन स्टॉफ द्वारा बालिकाओं को सूक्ष्म व्यायाम एवं योगाभ्यास कराया गया तथा योग के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभों की जानकारी दी

गई। योग शिविर में बच्चों, बालिकाओं एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर डॉ विनय राहुल, योग प्रशिक्षक सुदेश मिश्रा, पुनीत सहित अन्य कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा। वहीं सखी वन स्टॉफ से नमिता यादव, पारुल सिंह, प्रियंका, रंजीत एवं रीना का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों को नियमित योगाभ्यास के माध्यम से स्वस्थ, निरोग एवं सकारात्मक जीवन अपनाने का संदेश दिया गया। योग शिविर का उद्देश्य बच्चों एवं बालिकाओं में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के साथ–साथ उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन एवं सकारात्मक जीवन मूल्यों का विकास करना रहा।

जिला चिकित्सालय के इकलौते फिजिशियन का इस्तीफा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बढ़ी चिंता

अयोध्या। जिला चिकित्सालय अयोध्या के इकलौते फिजिशियन डॉ. प्रशांत द्विवेदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।उन्होंने यह इस्तीफा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) को ईमेल के माध्यम से भेजा है। भीषण गर्मी और संक्रामक रोगों के बढ़ते प्रकोप के बीच इस्तीफे की खबर से स्वास्थ्य विभाग में चिंता बढ़ गई है।जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन करीब एक हजार मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं, जिनमें लगभग आधे मरीज फिजिशियन से परामर्श लेते हैं।दो माह पूर्व पूर्व सीएमओ डॉ. नानक सरन के सेवानिवृत्त होने और अन्य फिजिशियन डॉ. अरुण प्रकाश के स्थानांतरण के बाद मरीजों का पूरा भार अकेले डॉ. प्रशांत द्विवेदी पर था।हालांकि शासन की ओर से पुनर्नियोजन पर एक फिजिशियन की तैनाती की गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। सीएमएस डॉ. राजेश सिंह ने बताया कि डॉ. प्रशांत ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा भेजा है, जिसे फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है।उन्होंने कहा कि अस्पताल में फिजिशियन की कमी लंबे समय से बनी हुई है और इस संबंध में उच्चाधिकारियों को कई बार पत्र भेजा जा चुका है।वहीं अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ. बृजेश सिंह चौहान ने मामले की जानकारी न होने की बात कही।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया थाना बाबा बाजार के आधुनिक भवन का लोकार्पण

अयोध्या। उत्तर प्रदेश में कानून–व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया।प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जनपद अयोध्या के थाना बाबा बाजार के नवनिर्मित अत्याधुनिक भवन का भव्य लोकार्पण किया गया।यह नवीन भवन उत्तर प्रदेश पुलिस को हाई–टेक बनाने और आम जनता को त्वरित व सुलभ न्याय दिलाने के संकल्प को दर्शाता है।नवीन थाना भवन की प्रमुख विशेषताएं व आधुनिक सुविधाएं इस नवनिर्मित परिसर को आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।जिसमें निम्नलिखित प्रशासनिक ब्लॉक व कार्यालय कक्षरू

पुलिस कर्मियों के सुचारू कामकाज के लिए हाई–टेक ऑफिस स्पेस, जनसुनवाई और प्रशासनिक निर्णयों के लिए एक व्यवस्थित विशेष कक्ष। मिशन शक्ति केंद्ररू महिलाओं की सुरक्षा, सहायता और उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए समर्पित विशेष डेस्क। डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप त्वरित डेटा प्रोसेसिंग और ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के लिए। आवासीय सुविधाएं व आधुनिक पुलिस कर्मियों के बेहतर रहन–सहन के लिए नवनिर्मित महिला बैरक एवं पुरुष सुरक्षित हवालातरू सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार की गई आधुनिक हवालात। इस अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के तैयार होने से न केवल पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और जन–सुरक्षा को एक नई मजबूती मिलेगी। स्थानीय जनता के लिए भी पुलिसिंग का अनुभव अब अधिक सुगम और मित्रवत होगा।

देवरिया के तीन कॉलेजों पर कार्रवाई की लटकी तलवार

गोरखपुर, (संवाददाता)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध देवरिया जिले के तीन महाविद्यालयों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। यह मामला छात्रों की परीक्षा के विलंब शुल्क से जुड़ा है। डीडीयू प्रशासन ने तीनों कॉलेजों को नोटिस भेजकर बकाए का कुल 57.62 लाख रुपये मांगा है। भुगतान न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बताया जा रहा है कि यह मामला सत्र 2025–26 के विषम सेमेस्टर का है। बीआरडी पीजी कॉलेज, देवरिया, मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज, भाटपाररानी, एपी गुप्ता एवं गीता देवी महाविद्यालय ने दिसंबर–जनवरी 2025–26 में हुई विषम सेमेस्टर परीक्षाओं में समय से अपने छात्र–छात्राओं का फॉर्म पूरित नहीं किया। इन कॉलेजों के आग्रह पर अंतिम समय में प्रावधान के अनुसार 2000 रुपये प्रति छात्र विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म पूरित किए जाने का आदेश डीडीयू प्रशासन ने दिया था।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।